तापमान

भोपाल	24.0°	29.0°
इंदौर	23.0°	29.0°
जबलपुर	24.0°	31.0°
ग्वालियर	25.0°	28.0°
सागर	24.0°	30.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 248, पृष्ठ 12)
श्रावण, कृष्ण सप्तमी संवत् 2083
गुरुवार, 6 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... कवच योजना से किसानों को मिलेगा नया संबल...

व्यापार... सर्राफा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी में बदलाव ...

खेल... बुमराह की खराब फिटनेस से उनके वर्कलोड ...

देश-विदेश... ट्रंप के कैलिफोर्निया गोल्फ कोर्स...

खास-खबरें

ई-20 डीपफेक मामले में गडकरी को राहत

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ई-20 डीपफेक मामले में बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गडकरी से जुड़े कथित डीपफेक और मानहानिकारक ऑनलाइन पोस्ट को तत्काल हटाने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री का सोशल मीडिया पर बने रहना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने मेटा, एक्स और गूगल सहित संबंधित मंचों को निर्देश दिया कि वे विवादित सामग्री को तुरंत हटाएं।

महबूबा मुफ्ती के धरने पर भाजपा का हमला

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने पर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान उनके हाथ में तिरंगा उल्टा होने का दावा करते हुए भाजपा नेताओं ने उन पर निशाना साधा।

एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा स्थगित

नईदुनिया ब्यूरो, जम्मूः अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए जाने की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियाती कदम के तहत बुधवार को जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। हालांकि प्रशासन ने यात्रा एक दिन के लिए स्थगित करने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है।

7 से शुरू होगा दिल्ली विस का मानसून सत्र

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की दो रिपोर्ट, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित अधिसूचना और तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की कार्रवाई पर रोक; हाईकोर्ट के स्थगन आदेश भी निरस्त

सुप्रीम कोर्ट सख्त, भोपाल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का रास्ता साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि उसके आदेशों के समानांतर कोई अलग प्रक्रिया नहीं चल सकती। साथ ही हाईकोर्ट से विभिन्न मामलों में मिली अंतरिम राहत और स्टे आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने बताया कि अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में कानूनी अड़चनें आ रही थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समानांतर किसी प्रकार की समीक्षा या जांच प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की 10 सदस्यीय समिति गठित की थी।

समिति को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने और तब तक व्यापारियों को राहत देने के सुझाव पर विचार करना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम को अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, बावड़िया कलां सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। शहर में करीब 30 से 35 हजार ऐसी संपत्तियां चिन्हित हैं, जहां आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। नगर निगम पहले ही एक हजार से अधिक नोटिस जारी कर चुका है और अब अभियान तेज करने की तैयारी में है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

- आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी रहेगी।
- मप्र सरकार की 10 सदस्यीय समीक्षा समिति की कार्यवाही पर रोक।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के समानांतर कोई अलग समीक्षा या जांच प्रक्रिया नहीं चलेगी।
- हाईकोर्ट से मिले सभी अंतरिम स्टे और राहत आदेश निरस्त।
- निर्देश : निगम बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई जारी रखे।

इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर

नगर निगम की कार्रवाई का सबसे अधिक असर उन इलाकों में पड़ेगा, जहां वर्षों से आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इनमें अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर, कोलार, बैरागढ़, भेल क्षेत्र, विदिशा रोड, अशोका गार्डन, आनंद नगर, चुनाभट्टी और पुराने भोपाल के बाजार प्रमुख हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इन क्षेत्रों में निगम का अभियान और तेज होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मकानों का उपयोग दुकान, शोरूम, कार्यालय, क्लीनिक, गोदाम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में किया जा रहा है।

कार्रवाई का दायरा

- चिन्हित व्यावसायिक उपयोग वाली संपत्तियांः 30,000 से 35,000
- अन्य अनुमानित चिन्हित भवनः 35,000 से 40,000
- नगर निगम द्वारा जारी नोटिसः 1,000 से अधिक
- विस्तृत सर्वे के बाद संभावित प्रभावित आवासीय भूखंडः 70,000 से अधिक
- संभावित प्रभावित लोगः लगभग 3 लाख परिवार

प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मांगी माफी

- संसदीय समिति के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद कंपनी ने तकनीकी त्रुटि स्वीकार करते हुए जताया खेद

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो सोशल मीडिया मंचों से अस्थायी रूप से हटाए जाने के मामले में मेटा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। संसदीय समिति द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद कंपनी ने 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखते हुए घटना को तकनीकी त्रुटि बताया।मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से कंपनी की ओर से खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पर अस्थायी रोक लगना एक तकनीकी गलती थी, जिसे तुरंत सुधारते हुए सामग्री को दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे पहले संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के शीर्ष अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर भारत आने और इस मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा था।

आरपीएफ ही संभालेगी रेलवे सुरक्षा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी आगे भी रेलवे सुरक्षा बल के पास ही रहेगी। इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व आरपीएफ ही निभाता रहेगा।

एमवाय अस्पताल के फार्मासिस्ट पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति, नकदी और दस्तावेज मिले, विदेश यात्रा की भी जांच

नईदुनिया ब्यूरो, इंदौर : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में उनके पास वैध आय की तुलना में 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया है। मामले में दस्तावेजों की जांच और संपत्तियों का सत्यापन जारी है। ईओडब्ल्यू के अनुसार राकेश गोरखे की वर्ष 2007 में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हुई थी। जांच अवधि के दौरान उनकी और उनकी पत्नी की कुल वैध आय 1.11 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई, जबकि उनके पास लगभग 2.13 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। छापेमारी के दौरान टीम ने विभिन्न स्थानों पर स्थित दो मंजिला मकान, कई भूखंडों से संबंधित दस्तावेज, बैंक अभिलेख, पासपोर्ट और लगभग 1.51 लाख रुपये नकद जब्त किए। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संपत्तियों की जानकारी विभाग को नहीं दी गई थी। जांच के दौरान जब्त पासपोर्ट से यह भी पता चला कि राकेश गोरखे अक्टूबर 2023 में कथित तौर पर बिना विभागीय अनुमति थाईलैंड गए थे।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं से किया संवाद

अनुशासन और मेहनत को बताया सफलता की कुंजी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को टी.टी. नगर स्थित कमला नेहरू सांदीपनि शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के चेहरों पर उन्हें विकसित भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है और राज्य सरकार हर छात्र के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

डा. यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में आज के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य तय कर निरंतर परिश्रम करने का आह्वान किया और कहा कि पढ़ाई के साथ खेल, अनुशासित दिनचर्या तथा आत्ममूल्यांकन भी जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने लगातार अध्ययन जारी रखा और उच्च शिक्षा प्राप्त की।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संगीत कक्ष और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों का भविष्य गढने वाली प्रयोगशालाएं हैं।प्रश्नोत्तर सत्र में छात्राओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक मीडिया, करियर और अध्ययन से जुड़े प्रश्न पूछे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनों का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन तथ्यों की पुष्टि स्वयं करना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान देने की सलाह दी।

21 करोड़ की साइबर ठगी मामले में जिला पंचायत सदस्य हिरासत में

नईदुनिया ब्यूरो, शाजापुर : ग्वालियर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से 21.06 करोड़ रुपये की कथित साइबर ठगी मामले की जांच अब शाजापुर तक पहुंच गई है। स्टेट साइबर पुलिस की टीम ने जांच के सिलसिले में जिला पंचायत सदस्य जगदीश फौजी से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए ग्वालियर ले गई।

शाजापुर पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में जगदीश फौजी से जुड़े एक चालू खाते में लगभग 50 लाख रुपये के लेनदेन की जानकारी सामने आई है। इसी आधार पर साइबर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। फिलहाल मामले में जांच जारी है और किसी भी भूमिका का अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। स्टेट साइबर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जांच में एक बड़े साइबर गिरोह के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। पुलिस विभिन्न बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों की पड़ताल कर रही है तथा अन्य संदिग्ध खातों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लेने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मामले में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

असम में बाढ़ से 15 हजार हेक्टेयर से फसल बर्बाद मृतकों की संख्या 89 पहुंची

नईदुनिया ब्यूरो, गुवाहाटीः असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन नुकसान का दायरा अब भी बड़ा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में दो और लोगों की मौत के बाद इस वर्ष बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, वर्तमान में राज्य के पांच जिलों के 1.22 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिला है, जहां करीब 60 हजार लोग बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा चराइदेव में लगभग 31 हजार और जोरहाट में करीब 20 हजार लोग प्रभावित हैं। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है और चार जिलों में 55 राहत शिविर तथा राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 17,857 लोगों को आश्रय और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ से कृषि क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ है।

कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं बनेगी : दीपके

छत्रपति संभाजीनगर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि संगठन फिलहाल राजनीतिक दल नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि सीजेपी एक जन-दबाव समूह के रूप में काम करेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा मजबूत करने के लिए जन-आंदोलन चलाएगी।

अब सुप्रीम कोर्ट में 34 की जगह 38 न्यायाधीश होंगे

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः नई दिल्ली। राज्यसभा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हो जाएगी। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो चुका था। अब यह कानून मई 2026 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा कि देश में लगातार बढ़ रहे मुकदमों, न्यायपालिका पर बढ़ते कार्यभार और नए संवैधानिक व कानूनी मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया था। उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता जताई थी।

मंत्री के अनुसार, प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यदि न्यायाधीशों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तो आपराधिक और दीवानी मामलों के निपटारे में और अधिक विलंब हो सकता था। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या घटाना और सभी नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है।

सरकार ने बताया कि 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अध्यादेश जारी किया गया।

एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने टेवोल्डे गेब्रेमारियम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः एयर इंडिया ने टेवोल्डे गेब्रेमारियम को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। वे इससे पहले इथियोपियन एयरलाइंस समूह का सफल नेतृत्व कर चुके हैं और विमानन क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को एयर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कंपनी का कहना है कि टेवोल्डे गेब्रेमारियम के नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस ने तेज विस्तार किया, लाभ में वृद्धि दर्ज की और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। अब एयर इंडिया को भी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में परिचालन क्षमता, ग्राहक सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय विस्तार को नई गति मिलेगी।

बढ़ोतरी — *प्रति किलोमीटर दो रुपये तक वसूला जाएगा किराया, अधिसूचना जारी...*

प्रदेश में बस यात्रा हुई महंगी, नया किराया लागू

- बस किराए में बढ़ोतरी से यात्रियों पर बढ़ा बोझ
- बस संचालकों की हड़ताल की चेतावनी के बाद निर्णय

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में बस यात्रियों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में प्रति किलोमीटर 75 पैसे की वृद्धि कर दी है। नई दरों के अनुसार अब यात्रियों से प्रति किलोमीटर दो रुपये तक किराया लिया जाएगा। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही संशोधित किराया तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई यात्री 100 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे पहले 125 रुपये किराया देना पड़ता था, जबकि अब उसी दूरी के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा। किराया वृद्धि का निर्णय मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की सात अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल की चेतावनी के बाद लिया गया है। दो दिन पहले परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई थी। बैठक में किराया बढ़ाने पर सहमति बनी थी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पांडेय ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से बस किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिससे छोटे बस संचालकों के लिए डीजल का खर्च निकालना भी कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि संगठन ने सरकार के समक्ष पांच मांगें रखी हैं। यदि शेष मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो सात अगस्त की मध्यरात्रि से प्रदेशभर में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। एसोसिएशन ने 40 मार्गों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति देने तथा पूर्व में जारी अधिसूचना निरस्त करने की भी मांग की है।

लोकसभा सचिवालय के निदेशक गौतम फ्लैट में मृत मिले

नईदुनिया ब्यूरो, नोएडाः नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में लोकसभा सचिवालय के निदेशक गौरव गौतम अपने फ्लैट में मृत पाए गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय गौरव गौतम लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। घटना के समय उनकी पत्नी मायके गई हुई थीं। घर लौटने पर फ्लैट अंदर से बंद मिला। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की सहायता से दरवाजा खोला गया, जहां गौरव गौतम अचेत अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को फ्लैट से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस का कहना है कि नोट की प्रामाणिकता और उसमें लिखी गई बातों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नोट में कर्ज का उल्लेख होने की बात सामने आई है।